

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 320] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर, 29, 1973/पीच 8, 1895

No. 320] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 1973/PAUSA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 29th December 1973

SUBJECT.—Setting up a High-powered Study Team to study the problems of the Handloom Industry.

No. 4/100/73-Tex.IV.—The Fifth Five Year Plan has emphasised that high priority should be given to programmes which provide maximum employment and are aimed at raising the income levels of those sectors of society which are living at present below the poverty line. In order to achieve these objectives, it has been decided *inter alia* that special attention be paid to the development of handloom sector. The All India Handloom Conference held in New Delhi on the 20th September, 1973 which was attended by prominent non-officials from the handloom field and by senior officers from the State and Union Territories, had also recommended that the problems of handloom industry and the weavers should be studied in depth before development schemes for the Fifth Plan period could be formulated.

2. In pursuance of the foregoing, Government have decided to constitute a High-powered Study Team to study the problems of the handloom industry and weavers. The study Team will consist of the following—

Chairman

- (1) Shri B. Sivaraman, Vice-Chairman, National Commission on Agriculture and Member, Planning Commission, New Delhi.

Members

- (2) One representative each of the Government of:
 - (i) Andhra Pradesh
 - (ii) Assam
 - (iii) Jammu & Kashmir.
 - (iv) Karnataka.

- (v) Maharashtra.
- (vi) Manipur
- (vii) Tamil Nadu, and
- (viii) Uttar Pradesh

(NOTE.—The State Governments concerned will be represented on the Study Team by the senior most officers dealing with handlooms, preferably of Secretary's rank)

- (3) Shri Konda Lakshman Bapuji 'Jayabharusayam' 6-1-2/1, Secretariat Road, Hyderabad.
- (4) Shri Abid Ali Ansari, M.L.A. 27-Daraul Shaifa, Lucknow.
- (5) Smt. Pupul Jayakar Chair, Handicrafts and Handlooms Export corporation, Rouse Avenue, New Delhi.
- (6) Shri M. Somappa, President, All India Handloom Fabrics Marketing Cooperative Society Ltd., 211-219, Bharti Bhavan, Frere Road, Bombay-400001.
- (7) Shri T. R. S. Vijayaraghavachari, Director, Tamil Nadu Handloom Finance and Trading Corporation, Ltd., Madras.
- (8) Shri Mani Narayanswami, Joint Secretary, Ministry of Commerce, New Delhi.
- (9) Shri S. K. Bagchi, Textile Commissioner, Post Box No. 11500, Bombay-400020.

Member-Secretary

- (10) Shri A. N. Varma, Director, Ministry of Commerce, New Delhi.
3. The terms of reference of the Study Team shall be.
- (i) To suggest programmes for development of the handloom industry in the Fifth Plan;
 - (ii) To suggest measures for the maximum utilisation of the export potential of the handloom sector;
 - (iii) To suggest measures for building infra-structure and providing adequate inputs, particularly finance to the handloom sector; and
 - (iv) To review the position regarding reservation and to suggest changes in policy, if necessary.
4. The Study will submit its report as expeditiously as possible but latest by the 31st March, 1974.

ORDER

Ordered that the Resolution shall be published in the Gazette of India.

Ordered also that copies of the Resolution shall be sent to all concerned

R. TIRUMALAI, Add. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1973

विषय :—हथकरघा उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उच्चशक्ति प्राप्त अध्ययन दल की स्थापना।

सं० 4/100/73-डैकम-4.—पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि उन कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनसे अधिकतम रोजगार की सुविधायें उपलब्ध होती हैं और जिनका उद्देश्य समाज के उन वर्गों की, जो इस समय निर्धनता के स्तर से नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं, आय के स्तर बढ़ाना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए

अन्य बातों के साथ साथ यह विनिश्चय किया गया है कि हथकरघा क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाये। 20 दिसम्बर, 1973 को नई दिल्ली में जो अखिल भारतीय हथकरघा सम्मेलन हुआ था और जिसमें हथकरघा क्षेत्र से प्रमुख गैर-सरकारी अधिकारियों और राज्य तथा संघ-राज्य क्षेत्रों से वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था, उसमें भी यह सिफारिश की गई थी कि पांचवीं योजना अवधि के लिए विकास योजनाएं बनाने से पूर्व हथकरघा उद्योग तथा बुनकरों की समस्याओं का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए।

2. उपर्युक्त के अनुसरण में सरकार ने हथकरघा उद्योग तथा बुनकरों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्चशक्ति प्राप्त अध्ययन दल गठित करने का विनिश्चय किया है। अध्ययन दल में निम्नांकित होंगे :—

अध्यक्ष

1. श्री वी० शिवरामन,

उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा

सदस्य, योजना आयोग, नई दिल्ली।

सदस्य

2. इन सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि।—

(1) आंध्र प्रदेश

(2) आसाम

(3) जम्मू तथा काश्मीर

(4) कर्नाटक

(5) महाराष्ट्र

(6) मणिपुर

(7) तमिल नाडू तथा

(8) उत्तर प्रदेश

(नोट.—संबन्धित राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व अध्ययन दल में हथकरघा सम्बन्धी कार्यों को करने वाले सब से वरिष्ठ अधिकारी, विशेषतया सचिव के स्तर के अधिकारी करेंगे)

3. श्री कोन्डा लक्ष्मण बापूजी,

‘जयाबाळू सयाम’

6-1-2/1, सेन्टेटेरियेट रोड,

हैदराबाद :

4. श्री आबिद अली अंसारी,

सदस्य विधान सभा,

27, दादल शफा, लखनऊ :

5. श्रीमती पुपुल जयाकार;

अध्यक्ष,

हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम,

राउज एवेन्यू, नई दिल्ली :

6. श्री एम० सोमप्पा,
अध्यक्ष, अखिल भारतीय हथकरघा,
वस्त्र विपणन सहकारी समिति लि०,
211-219, भारतीय भवन,
फरेरे रोड, बम्बई --400001.
7. श्री टी० आर० एस० विजयराघवाचारी,
निदेशक, तमिलनाडु हथकरघा वस्त्र तथा व्यापार निगम, लि०,
मद्रास :
8. श्रीमणि नारायणस्वामी,
संयुक्त सचिव,
वाणिज्य मन्त्रालय,
नई दिल्ली ।
9. श्री एस० के० बागची,
वस्त्र आयुक्त,
पी० बा० सं० 11500,
बम्बई-400020.

सदस्य--सचिव

10. श्री ए० एन० वर्मा,
निदेशक,
वाणिज्य मन्त्रालय,
नई दिल्ली :
3. अध्ययन दल की शर्तें ये होंगी :—
 - (1) पांचवीं योजना में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम सुझाना ;
 - (2) हथकरघा क्षेत्र की निर्यात सम्भाव्यता से अधिकतम उपयोग के लिए उपाय सुझाना ;
 - (3) हथकरघा क्षेत्र के लिए अवस्थापना का निर्माण करने तथा पर्याप्त अन्तर्निवेश विशेष रूप से वस्त्र प्रदान करने के लिए उपाय सुझाना ; और
 - (4) परिरक्षण सम्बन्धी स्थिति का पुनर्विलोकन करना तथा यदि आवश्यक हो तो नीति में परिवर्तन सुझाना :
4. अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र लेकिन देर से देर 31 मार्च, 1974 तक प्रस्तुत करेगा :

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।
यह आदेश भी दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियां सभी सम्बन्धों को भेजी जायें ।

आर० तिरुमलाई, अपर सचिव ।